दूसरा संस्करण छापने का अधिकार लेखक के न चाहने पर भी अदालत से प्राप्त कर सकता है। इन ज्यादतियों को रोकने के लिए कापीराइट कानून से सम्बन्धित धाराओं के संशोधनों की आवश्यकता है। मेरी प्रार्थना है कि लेखकों के हितों की रक्षा हेतु एक विधेयक अगले सप्ताह सदन में लाया जाए।

SHRI BUTA SINGH : I am grateful to the hon. Members who have mentioned the matters of vital public importance through their points. The House is seriously engaged in having general debate on Finance Bill. All these matters form part of the debate. I will request them to hand over these points to the respective speakers of their parties so that they can highlight those points during their debate and it could attract the attention of the Government and the Ministry of Finance.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : My party spokesman has already participated in the Finance Bill. How can I hand over my points to him ?

SHRI BUTA SINGH : For having them included in the next week's programme, I can carry these points and I will definitely place them before the Business Advisory Committee. In case Business Advisory Committee finds time, they may do so. I will carry these points but at the same time I will request the hon. Members to have these points mentioned in the course of general discussion on the Finance Bill so that they can get the attention of the Minister of Finance because most of the items are primarily connected with the Ministry of Industry or Finance. These things can be taken care of during this debate.

MR. CHAIRMAN : Now we take up further consideration of the motion moved by Shri Pranab Kumar Mukherjee. Shri Girdhari Lal Vyas.

14.06 Hrs.

FINANCE BILL, 1983—*Contd.*

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कल माइका इण्डस्ट्रियल ट्रेडिंग कार्पोरेशन के बारे में जिक्र कर रहा था कि यह पब्लिक सेक्टर की कार्पोरेशन है जो माइका में डील करती है। राजस्थान में भीलवाड़ा जो मेरी कांस्टीटुएन्सी है, उसमें माइका सबसे ज्यादा निकलता है। यह कारपोरेशन बड़े-बड़े पूंजीपतियों से तो माइका खरीदती है लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं उनकी माइका नहीं खरीदती है। जब उनकी बिक्री नहीं होती है तो खानें कैसे चलेंगी ? उनकी खानें बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर की कार्पोरेशन इस तरीका का धंधा करे कि पूंजीपतियों से मिलकर उनका सामान खरीदे और छोटी-छोटी खानों के जो मालिक हैं, उनका सामान न खरीदे जिससे कि उन्हें खान बन्द करनी पड़े और फिर हजारों मजदूर बेकार हों तो यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि कार्पोरेशन के रेप्रेजेन्टेटिव्ज के द्वारा जो धांधली चल रही है उसको ठीक किया जाए और जो गरीब लोगों की माइका है, जो पांच नम्बर से नीचे है उसको भी खरीदा जाए। जो कम नम्बर की और हल्के दर्जे की माइका है उसके बारे में पहले भी कहा गया था और भारत सरकार ने आदेश भी दिया था कि 5 नम्बर से नीचे की जो माइका है उसको खरीदा जाए और एक्सपोर्ट किया जाए। आपने अपनी रिपोर्ट में जो वीकर शेक्संस को लाभ पहुंचाने की बात कही है उसके विपरीत यह काम हो रहा है इसलिए इसके बारे में तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो माइका निकलती है उसके आधार पर माइका पेपर के कारखाने वहां स्थापित किए जाने चाहिये। हजारों टन माइका वेस्ट वहां पर पड़ी हुई है जिस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, केवल कागज बनाने में ही उसका उपयोग हो सकता है। जिस प्रकार से बिहार में माइका पेपर के कारखाने स्थापित हुए हैं उसी प्रकार से भीलवाड़ा में भी माइका पेपर के कारखाने स्थापित किए जाने

चाहिए ताकि वहां पर पड़े हुए हजारों टन माइका वेस्ट का उपयोग हो सके और उसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भी मिल सके तथा हजारों मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध हो सके। इसकी तरफ आपको विशेष तवज्जह देनी चाहिए।

एक बात मैं जिंक-ओर के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अन्दर रामपुरा अगूचा में इस के बहुत बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं। जो कि करीब छः करोड़ टन के हैं। डिपॉजिट्स को देखते हुए वहां पर सुपर-जिंक-स्मेलटर-प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता है। आपने एक जर्मन टीम वहां भेजी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस का कारखाना चित्तौड़ में लगाया जाना चाहिये। लेकिन सरकार को इस बात का अन्दाजा नहीं है कि चित्तौड़ में कारखाना स्थापित करने से ढुलाई में कितना खर्चा आएगा। यदि इस को आगूचा में स्थापित किया जायेगा तो ढुलाई में खर्चा भी कम आएगा और बहुत कम पैसे में इसको यहां स्थापित किया जा सकता है। पता नहीं सरकार किस तरीके से इस को आंकती है। जर्मन टीम ने कह दिया और उसको वहां स्थापित करने के बारे में निर्णय ले लिया। वहां आपको इसके लिए अलग से पावर प्लान्ट लगाना होगा, पानी की व्यवस्था करनी होगी। ये व्यवस्थायें तो आपको वहां भी करनी पड़ेंगी लेकिन ढुलाई में जो अधिक खर्च होता, वह बच जाएगा। पता नहीं आपने किन कारणों से इस सारी व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश की है मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तरीके से इसका कारखाना रामपुरा आगूचा में ही स्थापित करना चाहिये। राजस्थान सरकार ने पहले भी कहा था कि वहां पर थर्मल प्लान्ट लगाना है, एक बांध बनाकर पानी लाने की व्यवस्था करेंगे। जब वहां की स्थानीय सरकार यह कहती है, तो इस संबंध में आपको विचार करना चाहिए। ताकि यह व्यवस्था उचित हो और खर्चा भी कम पड़े और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रान्त है। वहां पर बिजली की बहुत कमी है। बिजली की कमी को देखते हुए आप को नये-नये थर्मल प्लान्ट लगाने चाहिए। वहां पर बहुत बड़ा लिग्नाइट का भंडार है। लेकिन आज तक इस संबंध में कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। थोड़े दिनों पहले हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि एक करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक करोड़ रुपये से क्या होगा? जब तक योजना कार्यान्वित न हो, जितना खर्चा होगा, उसकी स्वीकृनि न हो, तो किस प्रकार आप इसको स्थापित कर पायेंगे।

राजस्थान बिजली के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और वह पिछड़ा ही रह जाएगा। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि जितने भी हाईड्रल प्रोजैक्ट्स हैं, वे सबके सब मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हैं, इनसे हमें पूरा बिजली का हिस्सा नहीं मिलता है, इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिये। इसी की वजह से हमारे जितने भी कारखाने हैं, कपड़े का कारखाना है, कॉपर और सीमेंट के कारखानों में सौ फीसदी कट था। इसी बिजली की कमी की वजह से चार हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। यदि आप राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बिजली के संबंध में व्यवस्था करनी पड़ेगी। थर्मल पावर प्लान्ट लिग्नाइट पर आधारित लगाने की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। ताकि बिजली के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ न रहे।

बिजली के ही संबंध में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड और दूसरी इस प्रकार की जो एजेंसियां हैं, उनमें व्यवस्था उचित नहीं है, सुचारू रूप से नहीं हैं, इसी वजह से वहां पर चोरियां होती हैं। बिजली के ट्रांसमीशन में 40 प्रतिशत की कमी है। 40

परसेंट की कमी जिस विद्युत बोर्ड में हो, वह व्यवस्था किस प्रकार से ठीक प्रकार से चल सकती है। इसी तरह से अन्य बातों में भी गड़-बड़ियां हैं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड सफेद हाथी के तरीके से हैं। जिन को कोई काम नहीं दिया है, ऐसे 15 हजार मजदूर अगर मुफ्त में पैसा लें तो आप बतलाइये कि राजस्थान इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे व्यवस्थित रूप में चल सकता है। आप के रिसोर्सेज को ये सफेद हाथी खा रहे हैं। आप सैकड़ों करोड़ रुपये इन इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को दे रहे हैं, मैंने आप के सामने राजस्थान की एक्जाम्पिल दी है, लेकिन दूसरे राज्यों के इलै-क्ट्रिसिटी बोर्डों की भी यही हालत है। मेरा निवेदन है कि इन को सुधारने के लिये आप निश्चित तरीके से कोई कदम उठायें जिससे कि ये बोर्डस ठीक प्रकार से चल सकें।

राजस्थान का खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट 1967 में लगाया गया था। इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिये जिन किसानों की जमीनों को एक्वायर किया गया था, आज तक उन को मुआवजा नहीं मिला है। आप के अधिकारी उन को हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट तक ले गये। इस प्रोजेक्ट को बने 15 साल हो गये, उन गरीबों को मुआवजा शीघ्र से शीघ्र मिलना चाहिये। जमीन एक्वायर करते समय उन के साथ यह वायदा भी किया गया था कि जिन की जमीन एक्वायर की गई है, प्रत्येक काश्तकार के घर के एक आदमी को काम दिया जायेगा, उन को काम भी नहीं मिला है। इस पब्लिक सैक्टर में जितने अधिकारी लोग हैं वे इस प्रकार रहते हैं जैसे पहले राजे-महाराजे रहते थे, बड़े ठाट-बाट से रहते हैं। इन के ठाट बाट को कम कीजिये ताकि उस से जो पैसा बचे वह देश के काम आये। आप ने उन को स्वायत संस्था बना कर ऐसी छूट दे दी है जिस से उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है।

1978 में, जब जनता पार्टी का शासन था, इस प्राजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 35 हजार कापर-रिवेट्स, जिन की असली कीमत 35 हजार रुपये प्रति टन थी, 21 हजार रुपये प्रति टन में लन्दन बेच दिया, इस प्रकार 21 करोड़ रुपये की गड़बड़ की। हम ने उस के खिलाफ आवाज उठाई। पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी ने भी कहा कि इस प्रकार के गलत काम अधिकारी लोग करते हैं, उन को निश्चित तरीके से सख्त-से-सख्त सजा मिलनी चाहिये, लेकिन अभी तक उस के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसी तरह मैंने एफ० सी० आई० के बारे में भी सदन का ध्यान दिलाया है। 1982 में राजस्थान के अन्दर फूड-एण्ड सिविल-सप्लाईज डिपार्टमेंट और एफ० सी० आई० ने मिल कर 80 हजार टन चावल रिजेक्टेड मान कर एक्जेंम्प्शन स्लिप ईशू कर दी। बाजार में वह चावल 400 रुपये क्विटल के भाव में बिका, जब कि आप के लेवी चावल का भाव 153 रु० क्विटल है। इस मे कितने रुपयों का नुकसान हुआ है आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आप एफ० सी० आई० को 500 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में देते हैं जब कि वहां पर इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है। जो लोग इस तरह की गड़बड़ करते हैं उन के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये।

हमारे भीलवाड़ा में राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स है जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी थी। उस के मालिकों ने उस कम्पनी को अपनी प्राइवेट प्रापर्टी बना लिया है और शेअर-होल्डरों का सारा पैसा डकार गये हैं। फाइ-नेन्स मिनिस्टर साहब को भी इस बारे में लिखा था लेकिन अभी तक कोइ कार्यवाही नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही कीजिये।

समाननीय सभापति महोदय, आखरी बात मैं फैमिन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी राजस्थान गई थीं और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि राजस्थान के अन्दर कितना भयंकर अकाल है। वहां पीने के पानी की बहुत कमी है, जान-वरों के लिए घास नहीं है और अनाज के लिए पानी नहीं है और दूसरी जो आवश्यक चीजें हैं,

सूखे के कारण उन की बहुत कमी हो गई है। इसलिए आप को पूरी सहायता राजस्थान को देनी चाहिए तब जा कर राजस्थान का इतना मुश्किल का समय निकल पाएगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो हैंड पम्प लगे हैं, उन में से 75 परसेन्ट सूख गये हैं उसके कारण एक बूंद पानी नहीं हैं। श्री बूटा सिंह के विभाग ने 43 करोड़ रुपया इन पानी के हैंड पम्पों के लिए दिया है लेकिन वहां पर लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है और अगर यही हालत रही तो बहुत से लोग प्यासे मर जायेंगे। भारत सरकार ने जो रुपया दिया है, उस का उपयोग किस तरह से हो रहा है, इस को सरकार को देखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस फाइनेन्स बिल का समर्थ करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, देश का जब तक संतुलित विकास नहीं होगा, तब तक बहुत सी समस्याएं भयंकर रूप में हमारे सामने आती रहेंगी, जैसे आसाम की समस्या है। उसका भी संतुलित विकास नहीं हुआ देश के दूसरे भागों के मुकाबले में। इसलिये मेरा यह कहना है कि देश के जितने पिछड़े जिले हैं और जिनके बारे में सरकार को जानकारी है, उन सभी का विकास भी उसी प्रकार से होना चाहिये, जिससे कि वे दूसरे जिलों के मुकाबले में आगे आ सकें। आज स्थिति यह है कि किसी जिले में तो चार-चार और पांच-पांच उद्योग लग गये हैं और किसी जिले में एक भी उद्योग नहीं है। मैं उनका नाम लेकर यहां पर कोई कान्ट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सभी स्थानों पर संतुलित रूप से अगर उद्योग नहीं लगाए जाएगें, तो कोई जिला पिछड़ा रह जाएगा और कोई जिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब जनता को कष्ट होता है, तो एक भावना पैदा होती है कि जहां रूलिंग पार्टी का कोई विशिष्ट आदमी है, वहां उद्योग लग जाएंगे और दूसरे स्थानों पर जहां उनका आदमी नहीं है, तो उद्योग नहीं लगेंगे।

मेरा जिला पीलीभीत है और शाहजहांपुर में पुवांया तहसील है और वहां पर एक नई चीनी मिल खुलने की बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिफारिश की है और स्थान का चयन करके भेज दिया है सर्वे करने के बाद लेकिन आज तक पुवांया में चीनी मिल का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यू०पी० गवर्नमेंट ने आई० आर० डी० स्कीम को लागू करने के लिए, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है, लिखा है कि बैंक आफ बड़ोदा की एक ग्रामीण बैंक की शाखा पीलीभीत में खोली जाए। ऐसा प्रोपोजल रिजर्व बैंक को गया हुआ है पर कई महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है और सभी जानते हैं कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मेरा कहना यह है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए एक स्पेशल मास्टर प्लान बनाना चाहिए और उनकी एक सूची बनानी चाहिये और पिछड़े हुए जिलों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ जिला है, उसे पिछड़ा माना जाना चाहिए। पीलीभीत पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन रायबरेली को पिछड़ा मानकर वहां पर उद्योग लगाने वालों का सब्सीडी दी जाती है और पीलीभीत में उद्योग लगाने वालों को कोई सब्सीडी नहीं दी जाती।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। किसानों को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। खाद, ट्रैक्टर, बिजली और पानी, इन सब की कीमतों में आप बराबर बढ़ोत्तरी कर रहे हैं। जब ऐसी बात है, तो फिर किसान कैसे सुखी होगा और अपना उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी कीमतें कम करे। आज एक ट्रैक्टर 1 लाख रुपये के करीब मिल रहा है और आइसर ट्रैक्टर, जो सब से छोटा है, वह 55000 रुपये और 56000 रुपये का हो गया है।

अगर उसके सब कल-पुर्जों को मिलाकर आप ट्रैक्टर बनाना चाहें तो उसकी कीमत 30-35 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। खाद की कीमतें, पानी और बिजली की कीमतें सभी आसमान को छू रही हैं। बिजली भी कैसी है? हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली 6 घंटे आती है और उसका भी पता नहीं है कि शाम को 6 बजे आयेगी या रात को 9 बजे या 12 बजे आयेगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस बिजली का भी इन्तजाम करना चाहिए और यहां से उत्तर-प्रदेश के लिए स्पेशल तरीके से बिजली दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए।

श्रीमन् काम के होने में कितनी देर लगती है? तीन-चार महीने हो गये, मैंने पीलीभीत के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत उल्लेख किया था कि पीलीभीत को जाने का एक ही रास्ता है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, अलमोड़ा, पिथौरागढ़ सब तरफ से लोगों का वहाँ याताyat होता है इसलिए वहां रेलवे के ऊपर ओवर-ब्रिज बनना चाहिए। श्रीमन् इसका जवाब आया कि मामला दिखवाया जा रहा है। उस मामले को दिखवाये हुए तीन-चार महीने हो गये लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब आपने आवश्यकता मान ली तो पीलीभीत में ओवरब्रिज जल्दी बन जाना चाहिए। नहीं तो यह पिछड़ा जिला ऐसे ही रहेगा, इसका पिछड़ापन दूर करने की कोई कार्यवाही नहीं हो पाएगी।

श्रीमन् आर्म्स एक्ट बना हुआ है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। इसको राज्य सरकारें इम्प्लीमेंट कर रही हैं। शाहजहाँपुर, पीलीभीत बरेली, बदायु इन चार जिलों का मुझे मालूम है कि इनमें आर्म्स के लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। जबकि मैं बोल रहा हूं तब भी वे बन्द हैं। कभी लाइसेन्स चार दिन को खोल देते हैं, फिर बन्द कर देते हैं। हम पूछते है कि क्या कोई सरकारी आर्डर है तो जवाब मिलता है कि चीफ मिनिस्टर की वरबल इन्स्ट्रक्शन्स हैं। चूंकि डकैतों का जोर है, इसलिए आर्म्स लाइसेन्स पब्लिक को नहीं दिये जाने चाहिए। गये साल में सौ लाइसेन्स भी नहीं दिए होंगे। तो क्या अब डकैतियां नहीं पड़ रही हैं? डकैतियां रोज पड़ रही हैं। लाइसेन्स न दिए जाने के बाद ये पड़ रही है। कहा जाता है कि लोग डकैतों को कारतूस सप्लाई करते हैं, राइफल सप्लाई करते हैं। आप जब लाइसेन्स देते हैं तो राइफल का नम्बर रजिस्टर होता है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल देखें तो जब चाहें उस लाइसेन्स को सस्पेंड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में देहातों में लोग थानों से 15-15, 20-20 मील दूर रहते हैं जहां कि पुलिस नहीं पहुंच सकती है। अगर उन लोगों के पास हथियार नहीं होंगे तो वे कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे। मेरा कहना है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहें कि वह इस तरीके से लाइसेन्स देना बंद न करे। वह अधिक से अधिक लोगों को लाइसेन्स दे जिससे कि देहाती क्षेत्रों में सुरक्षा हो क्योंकि डकैतियां बराबर पड़ती जा रही है। डकैतियां तभी पड़ती हैं जबकि पुलिस डकैतों से मिली रहती है, उनके साथ होती है। बन्दूक के लाइसेन्स देने से डकैतियां नहीं पड़ती हैं। (व्यवधान)

श्रीमन मैं एक बात कहना चाहता हूं। नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन का कार्यालय दिल्ली में है। उसमें एक सेक्रेटरी मिस्टर धवन साहब है। 15-20 सालों से वे ही सेक्रेटरी हैं। अब उनके पास तीन-तीन पद हैं। वे चीफ पर-सोनल मैनेजर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं और एक पद और है उनके पास। कायदे में उनके पास तीन पद नहीं हो सकते है। एक ही आदमी तीन-तीन पद लेकर विराजमान है। श्रीमन इस कारपोरेशन का काम विदेशों में चल रहा है फिर भी इसमें घाटा करोड़ों रुपये का है। लेकिन अपने अफसरों के लिए कोई घाटा नहीं है। एक-एक आदमी को बाहर भेजने पर किस तरह दस-दस रुपया लिया जाता है। किस तरह से चार और पांच बजे के बीच में सुरा और सुन्दरी का नाच होता है, आप

जाकर देख लीजिए। 10-10 साल से कैजुअल लेबरर काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर नहीं किया गया है। अभी 10-10 साल की सर्विस वाले 500 के करीब लोगों को निकाल दिया गया है। जबकि आपके आदेश हैं कि 2 साल की सर्विस के बाद उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। हम बाहर के देशों में भी इमारतें बना रहें हैं। इस तरह से इसमें घाटा नहीं होना चाहिए। इस ओर खास तवज्जह देने की आवश्यकता है।

स्मगलर्स ने हमारे देश की इकानामी को बहुत खराब किया है। ये लोग सरकार की आड़ लेकर और अपनी बुद्धि से देश की इकानामी को शैटर कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण है। अखबारों में छपता रहता है। यह 31 मार्च का प्रचण्ड साप्ताहिक है और सत्य लोकवाणी 3 फरवरी का है। दोनों कानपुर से छपते हैं। इसमें फ्रण्ट पेज पर छपा है** 106 करोड़ रुपए की भारी लूट।**

नए कारनामे।

PROF. K.K. TEWARY (Buxar): Sir on a point of order. My point of order is that charges are levelled only with the permission of the Chair. The hon. Member is levelling charges. Has he got the permission of the Speaker ?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I am referring to this paper. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Let us see what he is referring to. Mr. Gangwar, you cannot do that without the permission of the Speaker.

PROF. K.K. TEWARY : Has he got the permission from the Speaker to refer to this ?

MR. CHAIRMAN : Let us find out what he is saying. Mr. Gangwar, have you given any notice and obtained the permission ? You should not refer to any person who is not a Member of the House.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I am referring to this paper. I am not making any allegations of my own here. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Let me hear one by one.

PROF. K.K. TEWARY : You have upheld my point. You have to educate him that for such reference, he has to take the permission of the Speaker.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I do not want to be educated by you.

MR. CHAIRMAN : Mr. Gangwar, please do not refer to anything.

श्री हरीश कुमार गंगवार : जो इसमें लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूं। अपनी तरफ से कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूं। इसमें लिखा है—जबर्दस्त विज्ञापन बाजी के आधार पर लोहिया मशींस लिमिटेड ने वेस्पा एक्स-इ स्कूटर उपलब्ध कराने के नाम पर 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली फैक्ट्री के लिए 100 करोड़ रुपया एकत्र कर लिया है। इस फैक्ट्री की अभी नींव भी सरकार से मिली जमीन पर नहीं रखी गई है।

मैंने अपनी ओर से कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे मेरे मित्रों को दिक्कत हो रही है। क्या ये सारी चीजें गलत लिखी हुई हैं।

पृष्ठ 6 पर इसमें लिखा है कि जे. के. सिंथेटिक्स के प्रेसीडेंड ** ने अपने भांजे, भांजी और भाई के नाम पर लोहिया मशीन्स की स्कूटर फैक्ट्री का नाटक किया है।

** पुराने सम्बन्धों का लाभ उठाते हुए जनता को बेवकूफ बना दिया गया और एक अरब रुपया इकट्ठा कर लिया गया। 10 वर्ष के बाद यह स्कूटर जनता को मिल पाएगा और तब इसकी सही कीमत का पता चल सकेगा। मौजूदा वेस्पा एक्स-इ खरीदने वालों की संख्या को देखते हुए 50 साल से अधिक का समय उनको स्कूटर मिलने में लग जाएगा।

**Not recorded.

MR. CHAIRMAN : Mr. Gangwar, have you given notice to mention the name to the hon. Speaker ?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : I am only referring to this paper.

MR. CHAIRMAN : By reading the paper, you cannot make an allegation. There is a procedure. You have mentioned this. But, do not go into details of it.

श्री हरीश कुमार गंगवार : मेरा कहना यह है कि लोहिया मशीस ने 9 करोड़ 83 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए और 300 करोड़ रुपये इकट्ठे किए और 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से स्कूटर बुकिंग के नाम पर एक अरब छः करोड रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन, आज तक इस कम्पनी के दो कमरे भी नहीं बने। कोई मशीन नहीं लगी स्कूटर कैसे बनाकर देंगे ? पचास बरस में भी इतने स्कूटर नहीं बन पायेंगे। जब लोग कब्र में पैर लटकाए पड़े होंगे तब स्कूटर के पैंडल पर कौन किक मारेगा ? इन्होंने जो बजाज स्कूटर्स और इटली की पिआगो कंपनी के साथ मिलकर जनता के साथ फ्राड किया है, उसको कैसे सर्व कर पायेंगे ? हमारे उद्योग मंत्री जी बड़े सीधे-सादे और भोले-भाले हैं। ये, उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उस जमाने में मैं एम० एल० ए० रहा हूं। वह इतने बड़े पूंजीपतियों के जाल में फंस गए होंगे उनका कोई दोष नहीं बड़े-बड़े लोग इन पूंजीपतियों के जाल में फंस जाते हैं। इस फर्म ने चालीस प्रतिशत सामान आयात करने का भी कंसेशन ले लिया है। इस अखबार में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आसाम स्कूटर ने भी लोहिया मशीन्स के साथ स्कूटर निर्माण का लाइसेंस (लैटर आफ इन्डेंट) प्राप्त किया था उसका स्कूटर तैयार है। आसाम स्कूटर कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होने के बावजूद अभी तक सरकार से स्कूटर बुकिंग की अनुमति नहीं मिली है। सिघानिया को लोहिया मशींस कंपनी को इजाजत मिल गई जबकि आसाम कंपनी ने काम भी आरम्भ कर दिया था, उनको इजाजत नहीं मिली। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाए। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इतना रुपया एक ही जेब में चला जाए और जनता मूर्ख न बने, यह गंभीरता से सोचने की बात है। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपके और हमारे ऊपर भी आयेगी।

इसी प्रकार पिछले साल एक लाख 27 हजार मीट्रिक टन रशिया को मैसर्स रामा एसोसिएट्स, लारेंस रोड, दिल्ली के द्वारा चावल सप्लाई हुआ। परमल राइस को बाहर भेजने की इजाजत नहीं थी इसलिए उन्होंने बासमती राइस के नाम पर परमल राइस यहां से भेजा। एग्रीकल्चर का जो एगमार्क है, उसको जांच करने का अधिकार था, कामर्स मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है उसको भी देखने का अधिकार था लेकिन एक नोटिफिकेशन कर दिया गया कि इस मामले में बम्बई और दिल्ली की जो प्राईवेट कम्पनियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हालांकि मेरे पास है, उनको जांच करने का अधिकार दे दिया गया। बाद में सरकारी जांच संस्थान के काउन्टर सिगनेचर भी हो गए। भगवान जाने, यह कैसे हो गए ? बहरहाल, तमिलनाडु, केरल और दूसरे प्रदेश इस चावल के लिए तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लेकिन इस देश का एक लाख 27 हजार मीट्रिक टन चावल पिछले साल चला गया। उस समय 5500 रुपए बासमती और तीन हजार रुपए पर-मीट्रिक टन परमल का दाम था। बीच में 2500 पर मैट्रिक टन लोगों की जेब में चला गया। मेसर्स रामा एसोसिएट्स ने इस तरह से 50 करोड़ 10 लाख रुपया एक साल में कमाया। इस साल अस्सी हजार मैट्रिक टन फिर उसने सप्लाई किया। इस साल 6000 रुपये पर मैट्रिक टन बासमती का दाम है और तीन हजार परमल राइस का दाम है। परमल को बासमती के स्थान पर सप्लाई करके तीन हजार रुपया पर मैट्रिक टन एक ही फर्म मै० रामा एसोशियेटिड दिल्ली फिर बना रही है। देश में परमल चावल की

कमी है। जब परमल चावल की मांग की जाती है तो कह दिया जाता है कि इसकी कमी है। लेकिन इस साल जो देश से चला गया उसमें उसने 24 करोड़ बना लिया है। मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा है कि इसकी होम मिनिस्टर साहब से कह कर सी. बी. आई. से जांच कराइये। कांडला पोर्ट पर जो चावल गया है वह पड़ा है। इसकी जांच आपको चाहिये कि आप कराएं। एक गैंग बना रखा है। अगर कोई देख कर शिकायत करता है कि बासमती चावल के बारे नहीं है और गड़बड़ यहां की गई है तो उसको ट्रांसफर करा दिया जाता है या फिर रुपया देकर उसका मुंह बन्द कर दिया जाता है। बासमती के स्थान पर परमल चावल हिन्दुस्तान से बाहर चला गया। रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी वह दूसरे तरीकों से चावल ले सकता है चावल सहायता के रूप में फ्री भी दिया जाता है। भारत की प्रतिष्ठा को भी वह डाउन नहीं करना चाहता किसी भी सूरत में यह कह कर कि यहां लोग गड़बड़ी कर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं बड़-बड़े अफसरों का ऐसा काम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों स्कैंडलज को जो बहुत बड़े स्कैंडल्स भारत के पिछले दो साल के इतिहास के हैं, इनकी पूरी जांच सी. बी. आई. से कराई जाए और जांच कराने के बाद जो दोषी व्यक्ति हैं, उनको दंड दिया जाए।

SHRI RAJIV GANDHI (Amethi): Mr. Chairman, Sir, I stand to support the Finance Bill and I would like to concentrate on three main aspects of the Bill, agriculture, industry and energy. Before I start I would like to say that a very large portion of our economy is totally uncontrolled by the Government. We have taken certain measures to reduce it, but this is an area where substantial thought is required. Unless we can harness all the finances that are currently being used unproductively, we will find it very difficult to progress at the rate we want to progress. We have also to look at some of the promises that we had made in our manifesto. One of the major promises was that we would rationalise sales tax, and although it does not come directly under the Finance Minister. I hope he will take active measures in coordination with the various States so that we can rationalise sales tax and reduce the leakages that take place, because of the extremely complicated laws and the extremely complicated forms that have to be submitted.

In agriculture, there has been a full in our production. We went upto 126 million tonnes in 1977, and we have not improved substantially since then. We have very great disparities between the various States. We have Punjab, which grows approximately 3000 kgs. of wheat per hectare and on the other hand there is Madhya Pradesh with barely 900 kgs. of wheat per hectare. Similarly, in the case of rice Punjab grows 3000 kgs. as against Bihar which grows only 780 kgs. per hectare. If we are to again start accelerating the rate of increase of our food production, we have to concentrate in these areas where the production is low. We have to see that the correct inputs like irrigation and fertilisers are made available. We have a scheme under which six new fertiliser plants are planned, but I am told that there is a substantial delay in their implementation. The target date for completion is now around 1987 or 1988 and the last one is in my Constituency. I would request the Minister to try and expedite the completion of these fertiliser plants so that correct amount of fertilisers is made available.

In U.P. we have done a lot of work in the field of irrigation and very soon water will be made available to almost every part of U.P. This is no good unless the required amount of fertiliser is also made available.

We are seeing a change in the cropping pattern. The farmers are succumbing to market pressures and there is a shift from food crops to cash crops. We have to look into this. I am told the maximum return comes from Eucalyptus, and, if we let this drift continue, we will find thousands of acres of land under Eucalyptus and none under food crops. Some control has to be introduced and some guidance has to be given to sort this out.

Another thing that has been happening with the agricultural sector is that we have been having drought years one after another. Further more this is the third year in

succession when we have had unseasonal rains and large amount of our foodgrains have been spoiled. I would submit that we should have a Commission which can look into these aspects, which can look into how we can once again mobilise the agricultural sector to start increasing our food production at the same sort of rate as that was achieved earlier.

The Commission could also look into how crops can be balanced. I am told Madhya Pradesh now has vast acres of land under Soyabean, but nobody is willing to pick it up. We have the same problem with sugar-cane. We have to control this.

The Commission could also look at how we can change our agricultural methods to avoid large damage by unseasonal rains or by drought. Unless we are able to solve these problems and unless we are able to increase the output of our Kisans, I believe our country will find it very difficult to remain united.

Another problem that comes to minal, which is normally considered a law and order problem these days, is the problem of the dacoit-infested areas. When we deal with dacoits in a purely law and order way, we are not getting to the root of the problem. There are some basic inherent socio-economic problems there which go back much farther than just the law and order situation as we see it today. We have to develop these areas. We have to develop them agriculturally, we have to develop them industrially. Roads, Communications—a basic infrastructure has to be developed there. Unless we are able to do this, we will not be able to solve these problems. Even if we can exercise control in one area, the problems will sprout somewhere else. We have to get to the root of the problem and solve it starting from there.

We have had a lot of new taxes put on our industry and there are very few new places where taxes could be imposed. We are already burdened very heavily and the Finance Minister has very severe problems in finding sources for more money.

We have about Rs. 24,000 crores invested in the public sector, that is in the public sector excluding the P & T., and excluding the Railways, which may have an equivalent amount invested in them. The return on public sector investment is very poor. We get about 2-1/2% ; and from this, if we subtract the return of the petroleum companies, then we lose 1-1/2%. This is one area where, with efficient working, we can raise a lot of money. If we could get approximately 10% returns, it would finance almost half of our 6th Plan.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : No ; ten percent is not possible.

SHRI RAJIV GANDHI : It is possible. If you look at some of the companies, they are producing returns. The unfortunate part is than when a company produces today, you try to bring the other companies up to match. The companies that are productive then start running at a loss and the circle continues. Nonetheless we can produce.

We have some public sector companies ; for example Air India which is in a totally competitive market. It has nothing to do with a closed, controlled economy. It is competing with all the airlines in the world ; and when almost every other major airline is running at a substantial loss, Air India is making a good profit. So, where there is good management, we do well ; and there is no reason why we cannot do well in all the public sector companies.

One of the reasons why our industry gets left behind is because of the delays involved in licensing, in getting into production. I have some figures here. I think they are quite starting even horrifying :

Bokaro Stage II is 83 months late ;
Bhilai Expansion is 87 months late ;
Trombay V is 58 months late, and
Haldia is 84 months late.

If we take an average inflationary rate of 10%, then on a project which is 84 months or seven years late, we are paying 70% extra-for that project.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) ; The compound rate is double.

SHRI RAJIV GANDHI : For example, Bokaro is going to cost us Rs. 691 crores extra. All this money means that the production cost of whatever we are making, is

going to be increased. When the production cost is increased, the user pays more ; and it really adds to the inflationary spiral. We have to see that the time involved in evaluating and in licensing is reduced. We quibble over small amounts of differences. May be, by a few crores of rupees one supplier might be cheaper, and another supplier might be more expensive ; but in evaluating that, we take three years ; and then there is no meaning in one supplier being cheaper than the other, because we are paying almost one-third more than what we would be paying in the first place. Not only that ; by the time we take a decision we get out-dated technology, because we have been arguing about it for so long. In the new time frame we could well get new technology. This applies much more to the faster moving field of electronics. I believe we spent two years in evaluating some electronic exchanges. In two years, I think we must have by passed at least 2 or 3 more never models for electronic exchanges.

So far we have done only technical evaluation ; we have not even looked at the financial evaluation. In the other electronics fields, the transistor, the integrated circuit, we have missed the bus. There is no way we can now catch up. Today, if we are going really to try, we can jump on the computer bandwagon. We have the infrastructure ; we have the people. We need a good push and incentives from the government. We need the tax structure to be rationalised so that it is more profitable to manufacture in India than to import from abroad. The tax structure, as it stands today, makes it more profitable to import ready-made machine to change the label and to sell it is India than to import raw materials or the parts and actually build it here. If you are going to continue in this manner, then we will miss the computer bus as well and this is something which I believe we cannot afford to do.

We have encouraged the small scale sector. Today, almost 26 per cent of our production is in the small scale sector. I am very grateful to the Finance Minister for retaining the Rs. 7.5 lakh excise limit that was there earlier. I request him to review this for the next year and try to increase the limit to take account of the inflation rate. The Finance Minister has thought fit to put 20 per cent disallowance on advertising and travel. I am very glad that he has taken it away from the travel and allowed travel. But, if he can totally remove 20 per cent. I think he would really be boosting industry. If that is not possible, then, at least, he should exempt the small scale industries from this disallowance.

The Small Scale Sector faces a very big challenge from the bigger industries, from many multinationals especially in the electronic field and they are not able to match the marketing knowhow and the marketing pressure that the large companies exert. They find it difficult in many cases to match the quality which the large factories get by mass production. So, they are at a very great disadvantage. Therefore if we can, at least, in a small way, help them with this, I think it would not be just a benefit for the small scale sector but would give a big boost to our industry.

Inherently, we are individualistic people, and if we concentrate on small scale, I think we can increase our production very substantially. Some thing which has come in for a lot of controversy recently is the incentives that have been given to non-resident Indians Non-resident Indians are a very strong part of our society. Just because they have left the country does not mean that they are no more Indians ; they are Indians, all of them ; almost all of them have their families here ; most of them are placed in very high positions abroad ; many are at the forefront of technology, at the forefront of science, wherever they are. This is a very big reservoir, a reservoir from which we have to draw not just money, but knowledge.

15.00 Hrs.

It helps the country when we get the technology that these people are developing and helping others develop abroad, back to India. We must give them good facilities for this. We must allow them—as we have done—to set up now industries and we must give them facilities—not just financial, but also in clearances avoiding the time lags that involved in' clearances. Because, once a person has got used to a quick acting bureaucracy, he finds

it very suffocating to come back and try to fight his way for two or three years just to be allowed to make some small components.

There is a lot of disparity between the taxes that our industrialists pay and the taxes that are paid by non-resident Indians. So when we give them certain facilities we should also try to look into the comparison between the two and try to remove the idiosyncracies and anamolies that come into this because if the two are to compete in an industrial environment then they must have similar opportunities.

There is a danger that certain forces; not necessarily will meaning, can take over many of our industries under the present laws. The dangers are very real and unless our financial institutions are careful, we will have foreign agencies, through Indians abroad, taking over companies which are running well. We must guard against, the potential liquidation of assets and the bleeding of these companies. We have to see that these forces are not allowed to do this, if necessary, by law. What would be better is to give the companies some additional protection. What we need are new technologies and now companies. We must welcome them. At the same time, we cannot afford to let the present companies be in a state of flux which they are in today. If we can, we should limit the total foreign holding—the non-resident holding—in these companies to two or three per cent, or less than two or three per cent. This would give them the stability that is required for continued growth. Of course, this should be quite apart from existing FEARA lans. If we can do this, we would really once more restore a sense of security to our industries.

Our industries suffer most because of lack of energy ; and unfortunately we have not been able to make enough headway in this sector. When the Congress Government came in three years ago, we were handed over power plants operating at 44.7 per cent, well below what they should have been operating at. Today we have increased the load factor to 49,8 per cent. But if you look at only the Centrally run stations, if you exclude the atomic power stations, then we find that the average is over 60 per cent. Again, where we have made an effort, we can do it. Unfortunately, the States are not able to do very well. If we could introduce better maintenance standards, may be training institutes for the personnel wno run the powerplants, rally professionalise management and maintenance staff in these power srations, we would be able to improve one load factors substantially.

Every time we put up a new power plant we calculate that we need so much power and then we put up a power plant. The power plant operates at approximately 50 per cent load factor. We get only half the power. Which means, half the industries and agriculture, which are expecting power do not get it. It also means that the power that is being delivered, costs double what it should have cost, because we put in double the capacity and we are utilising only half the capacity. We need a professional standard of management for all over power plants.

BHEL has done a lot of work in this field. Today, BHEL is not able to supply enough power plants to satisfy our needs. We are having to spend large amounts of money in importing these power plants. Although like some of our friends have said that it is very convenient and fun for people to go abroad and see the power plants, we would like that these power plants should be made here. If BHEL does not have the capacity, if their technology is not upto the standard, only then should we allow the impart of new plant. We should get the new tecnnology and let BHEL make the plants here so that we gain from that technology. Of course, BHEL's plants do not seem to work at the same level of productivity as imported plants, but we must consider that they have been making these plants for only a few years. It is only from that experience and it is only by building plants that they will learn to make them run better. If we do not give them a chance today, they will never be able to improve and we will, once again, be totally dependent on foreign countries for our power plants, which is something we cannot afford. We must give BHEL a good boost, get it to improve its production quality, get it new technology and get it to produce enough power plants to meet our needs.

We have done very well in the petroleum sector. Although we expected to be self-sufficient, we find that demand is increasing even faster than production. We have got five refineries which are to be upgraded and renovated and four new refineries in various stages of Completion. I would, once again, request that these be expedited.

We have a lot of coal. Unfortunately, we have to import large quantities of cooking coal. Here again we can improve our production so that imports are cut. The quality of coal has come in for a lot of criticism and I feel rightly so. One of the reasons for this is that the measure of coal production is in tonnes. The miner is under pressure to produce so many tonnes of coal. So, instead of digging out only the best coal, he also extracts a lot of rock. When this gets to the power station or the steel mill, it causes many problems, damage and cost. We should change this measure. We should measure output of coal in calorific value; in BTUs or in some such measure, so that only coal is actually mined. Or we could wash it and clean it at the source so that, once again, what is transported is only the good quality coal. If we are transporting 30 per cent raw, 30 per cent of the transport cost is being totally wasted, 30 per cent of the wagons are being misutilized and we can ill-afford to throw energy to the winds because it is energy which is being used to transport coal. Really we are wasting energy in transporting energy. We have to look at what are the best methods of transporting coal.

Lastly, I think the vital component in any system is the education system and we have not been paying enough heed to it. Our education system should have ensured by now proper national integration. We should have had a system where there was adequate vocational training, we should have had a system where agricultural practices were improved, we should have had a system where industrial technology would have developed at a sufficiently rapid pace. If we had a good system, it would also automatically control our population explosion. Fortunately, our existing system has functioned in some ways. Today we can be proud, as I said earlier, of Indians in top positions all over the world where 30 years ago, we could not have dreamt of this. Unfortunately within the country an existing education system is not giving us the strength that it should. What we need is a new thrust in this area. We need to review our system because it is only with good solid, useful education that we will be able to make anything else function optimally.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि वित्त विधेयक पर विचार करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ फिर से सदन और वित्त मन्त्री का ध्यान खींचा गया है। मुझे खुशी है कि मुझसे पहले अभी श्री राजीव गांधी ने कई बहुत रचनात्मक सुझाव दिये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मन्त्री जी, चूंकि वे उनकी पार्टी के महामन्त्री भी हैं, उनके सुझावों पर गम्भीरता से गौर करेंगे। शायद आज जरूरत इस बात की है कि बात सफाई से की जाय और उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय। इसलिये कि मैं ऐसा मानता हूं। पिछले दिनों में जो संकट हमारे देश में तेजी से बढ़ा है, वह केवल सतही संकट नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था का संकट है। आज जो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारे देश की प्रशासकीय व्यवस्था है, उसमें बहुत से मौलिक बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बावजूद इस के कि हमने देश में काफी मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न आज इस देश के सामने है कि जो साधन हमारे पास हैं उन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग इस देश के अन्दर नहीं हो रहा है। अभी कुछ उदाहरण राजीव गांधी जी ने दिये। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से हमारी बहुत सी योजनायें विलम्ब के कारण मंहगी हो गई हैं और देश को जो लाभ उन से होना चाहिये वह नहीं हो रहा है।

मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं—सिंचाई को लीजिए। कृषि की बात कही गई है, कृषि का सबसे प्रमुख अंग है—सिंचाई, जो उस की बुनियाद है, आधार है। जितनी योजनायें

हम ने पिछली 6 योजनाओं में बनाई, उनके हिसाब से ढाई करोड़ हेक्टेअर में सिचाई हो जानी चाहिये थी, लेकिन वे योजनायें पूरी नहीं हो सकीं और आज यह स्थिति है कि उनको पूरा करने के लिए 1400 करोड़ अतिरिक्त रुपये की आवश्यकता है। यदि वे योजनायें समय से पूरी हो गई होतीं तो न केवल ये 1400 करोड रुपए बचते बल्कि उन से जो ज्यादा उत्पादन होता उससे देश का राष्ट्रीय उत्पादन कहीं ज्यादा बढ़ सकता था।

तो देश का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है। आजादी के बाद 205 बड़ी सिचाई की योजनाएं देश में तैयार की गई लेकिन उन 205 योजनाओं में से केवल 29 ही पूरी हुई हैं। 205 योजनाओं में से 29 योजनाएं ही पूरी हो सकीं और शेष योजनाएं आज तक पूरी नहीं की जा सकी। इन योजनाओं में से 8 ऐसी बड़ी सिंचाई की योजनाएं हैं जो 15 और 20 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो सकी है और उन पर काम हो रहा है। उन पर 1221.45 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन क्योंकि समय से वे पूरी नही की जा सकी हैं इसलिये 923 करोड़ रुपए अतिरिक्त उन पर खर्च करने पड़ेंगे। यह हमारी स्थिति है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का हर विभाग के अन्दर एक मानीटेरिंग सैल बनाना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए कि जिन योजनाओं को पूरा होने का जितना समय है, वे समय से पूरी हों। अगर वे समय से पूरी नहीं होती हैं, तो कौन व्यक्ति उस के लिए जिम्मेवार है, कौन सी परिस्थिति इसके लिए जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी निश्चित होनी चाहिए। अब देश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतने अरब रुपए इस तरह से बर्बाद हो जाए। बहुत सी योजनाएं समय से पूरी नही हो सकी हैं और उन में से एक का उदाहरण मैंने दिया है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं चाहे वह इस्पात के क्षेत्र में हो और चाहे वह कोयले के क्षेत्र में हो बिजली की हालत तो और ज्यादा बुरी है। सिचाई की ओर दूसरी जो हमारी योजनाएं हैं, उनको पूरा होना चाहिए समय के अन्दर ताकि हमारे जो साधन हैं, उन का समुचित रूप से उपयोग हो सके।

PROF. N.G. RANGA : Inter-State disputes.

श्री चन्द्रजीत यादव : बहुत सही कहा आप ने। इन्टरस्टेट डिस्प्यूट्स जो हैं, वे भी जल्दी सेटिल होने चाहिए। क्या वजह है कि इनको जल्दी सेटिल नहीं किया जा सकता। क्या इस देश के अन्दर ऐसी परिस्थिति हम पैदा नहीं कर सकते बैठकर और आपस में चर्चा करके कि ये जल्दी निबट जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुख्य मन्त्री अपना मन बना लेते हैं, वहां ये मामले निबट जाते हैं और जहां मन नहीं बनता है, वहां पर चलते रहते हैं। अब देश इस बात को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हीं बातों से देश की प्रगति धीमी हो गई है और देश कमजोर हो गया है। अभी राजीव जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर काफी सिंचाई-व्यवस्था है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक-तिहाई हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है, बाकी जो दो-तिहाई खेत हैं, उनमें पानी नहीं जा सकता। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। वहां पर नहरें खुदी हैं लेकिन पानी नहीं मिलता क्योंकि बिजली 2-3 घन्टें से अधिक नहीं मिलती। किसानों की फसल सूख कर बर्बाद हो गई है। इससे न सिर्फ किसानों का नुकशान होता है बल्कि यह राष्ट्रीय नुकसान है और इससे देश का अहित होता है। आज इन सब बातों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

अब मैं मैन-पावर मोबीलाइजेशन के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमें इस बात का गौरव है कि हमारा किसान मेहनती है, हमारे नौजवानों में उत्साह है और वे परिश्रमी हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नीशियन्स, हमारे इंजीनियर, हमारे प्रशासक दुनिया के किसी भी

देश के मुकाबले में अच्छा काम कर सकते हैं मगर अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं हो रही हैं। उनकी क्षमता का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है इसलिए मेनपावर मोबीलाइजेशन स्कीम आप को ब्लाक लेविल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बनानी चाहिए और आने वाले 5-10 वर्षों के लिए इस की प्लानिंग होनी चाहिए। मेनपावर मोबीलाइजेशन की प्लानिंग आप कीजिए और उसको मोबीलाइज करके देखिये कि क्या होता है। पहले भूदान से काम होता था और कुछ श्रमदान से काम होता था लेकिन अब वे सारे काम छोड़ दिये गये हैं और सारे का सारा काम सरकारी नौकरों पर ही निर्भर रहेगा और जनता को हिस्सेदार आप नहीं बनाएगें, उनको सहायक नहीं बनाएगें, तो देश ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता है। मेरा कहना तो यह है कि अगर गांव में आपको स्कूल बनाना है, दो-तीन मील लम्बी सड़क बनानी है या कोई अस्पताल बनाना है, तो आप गांववालों से कहिये और इसके लिए आप एक-तिहाई या आधा हिस्सा श्रम के रूप अपना योगदान दीजिए और बाकी सरकार खर्च करेगी। इससे लोगों में उत्साह पैदा होगा। केवल नौकरशाही के ऊपर छोड़कर आप इस देश का संचालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इसका पता लगाइए और एक इंक्वारी कमीशन बैठाइए कि पिछले वर्षों के अन्दर जितनी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका क्या हुआ और कितनी वे पूरी हुई हैं। आज कुछ इंजीनियर इस बात के आदी हो गये हैं कि पहले उन्होंने 50 करोड़ रुपये की योजना बनाई और जब वह योजना स्वीकार हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि इस योजना को और आगे बढ़ाओ। इस तरह से जो योजना 50 करोड़ रुपए की थी, वह 200 करोड़ रुपये की हो जाती है। वक्त कटता जाता है चर्चाओं में और बातचीत में और काम नहीं होता है और जिस योजना को 3 साल में पूरा होना था, वह 10 साल में और 12 साल में भी पूरी नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि 50 करोड़ रुपये से शुरू की हुई योजना 500 करोड़ रुपये तक इस देश में पहुंच चुकी है। कौन इसके लिए जिम्मेवार है, यह निश्चित कीजिए।

आज कांट्रेक्टर्स और इंजीनियर्स दो ऐसी शक्तियां पैदा हो गयी हैं जो आधा रुपया खा जाती हैं। आप किसी भी सड़क को या केनाल को ले लीजिए। कांट्रेक्टर्स और इंजीनियर्स मिल कर आधा रुपया खा जाते हैं। पब्लिक का पैसा जो कि विकास कार्यों के लिए है, उस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और विकास का आधा भी काम नहीं हो पाता है। हमारा देश गरीब है। हमारे पास फण्ड्स का अभाव है। इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज आपको भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, इसके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहां कि विकास के कार्य हो रहे हैं और जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जा रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देना है।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह कहा था कि हम अपने देश में आर्थिक और सामाजिक शक्तियों का संचालन इस प्रकार से करना चाहते हैं कि इस देश में धन की शक्ति चंद हाथों में केन्द्रित न होने पाये, उनकी इजारेदारी न हो जाए। लेकिन आज इस देश में 16 फीसदी लोगों के हाथों में 90 फीसदी आय केन्द्रित होती जा रही है और इस देश में ऐसे भी गरीब आदमी हैं, 30-35 करोड़ आदमी, जिनकी 35 साल की आजादी के बाद एक दिन की आमदनी एक रुपया तक नहीं हो पायी है। यह इस देश के लिए सबसे शर्म की बात है, इसके लिए क्या योजना बनाई जा रही है? किस प्रकार से आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं? क्या आपने इसके बारे में ब्लाक के लिए कोई योजना तैयार की है कि अगर एक ब्लाक में सौ परिवार ऐसे हैं तो उनके लिए 50 हजार रुपये गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के

लिए आप साल में खर्च करेंगे ? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 21 वीं शताब्दी खत्म होने तक भी गरीबी को नहीं मिटा सकेंगे ।

हमारे देश में दस करोड़ लोग बेकार पड़े हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उनकी बेकारी दूर करने के लिये क्या योजना बन रही है ? आप समाजवादी देशों की बात छोड़ दीजिए, जहां यह समस्या नहीं है । क्या यह सच्चाई नहीं है कि दुनिया के हर देश में जो कि समाजवादी नहीं हैं, बेकार लोगों को बेकारी भत्ता दिया जाता है ? अमेरिका में एक महीने में 22 सौ रुपये, फ्रांस में 18 सौ रुपये, इंग्लैंड में 18 सौ रुपए, इटली में जिसकी कि अर्थव्यवस्था जर्जर हो गयी है, 17 सौ रुपये, स्वीडन में, नार्वे में 15 सौ रुपये बेकारी भत्ता दिया जाता है । हमारा देश आज अपने बेकार लोगों को 150 रुपया महीना भी बेकारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं है । मैं इस बात की मांग करता हूं और वित्त मन्त्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि जो हम चार सौ करोड़ रुपया तेल से बचा रहे हैं उसमें से कम से कम बेकारों को 150 रुपया मासिक बेकारी भत्ता दीजिए । कम से कम उन लड़कों को तो दीजिये जिनके परिवारों ने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया है और जिनके परिवारों के पास आय का पर्याप्त साधन नहीं है । मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी बेकारी भत्ते के मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे ।

श्रीमन् आज शहरों और गांवों का अन्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है । शहरों के अन्दर जीवन की सारी सुविधाएं, बिजली और पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं । शहरों की सड़कों को आप चमका रहे हैं, शहरों में खेल के लिए बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हैं लेकिन गांवों के लोगों को सड़कें, पीने के पानी जैसी सुविधाएं भी मुहत्तसर नहीं हो सकी हैं । आज इस देश में लाखों ऐसे गांव हैं जहां प्राइमरी स्कूल और हेल्थ सेन्टर नही बन सके हैं । मैं कहना चाहता हूं कि शहर और गांव के बढ़ते हुए अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार को आने वाले जमाने में गांवोन्मुखी योजनाएं बनानी पड़ेंगी । हमारे देश की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । रंगा साहब जैसे आदमी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे । इस देश में सरकार की जो प्राइस सपोर्ट पालिसी है, यह बड़ी खतरनाक पालिसी है । किसान को भेड़ियों के सामने डालने वाली यह नीति है । किसान को सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए । देश में एक मूल्य नीति निर्धारित होनी चाहिए । जिस प्रकार से उद्योगपति की कीमत उसके द्वारा तैयार माल की लागत कीमत और मुनाफा जोड़ कर निर्धारित होती है उसी प्रकार से किसान द्वारा पैदा की गयी चीजों की कीमत भी चीजों की लागत और मुनाफा जोड़ कर निर्धारित होनी चाहिए । तभी इस देश में परिवर्तन आ सकता है । आज देश के 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं ।

अभी राजीव जी कह रहे थे...

PROF. N.G. RANGA : Rao Birendra Singh said that Government is committed to it. But it is not being implemented.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : But they have no will power to implement. What does it mean ? I even disagree with the Rao Birendra Singh.

The Government is not committed to give a price based on remundrative price, which they are insisting. Rao Birendra Singh gave a statement here that they are supporting for the policy of support price which is the injustice done to the farmers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, you are concluding by 3-30 p.m.

श्री चन्द्रजीत यादव : दुसरी बात मैं देश के करों के ढांचे के बारे में कहना चाहता हूं । इस पूरे स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । गिफ्ट टैक्स, वैल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, इन सब पर विचार करने की आवश्यकता है । क्या वजह है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी-

बड़ी कंपनियों का टैक्स में योगदान कम होता जा रहा है ? आपने देखा होगा कि 1977-78 में बड़ी कंपनियों का सीधे करों में 55 प्रतिशत का योगदान था, जो 1981-82 में घटकर 48 प्रतिशत रह गया। बडी कम्पनियां जो टैक्स नहीं देती हैं उनकी 1979-80 में संख्या 35 थी जो अब बढ़कर 49 हो गई है। कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जैसे साराभाई कम्पनी का पूरा स्ट्रक्चर है और 22 ट्रस्ट हैं। नतीजा यह है कि सारी दौलत बंट जाती है और टैक्स बचाने का तरीका निकाल लिया जाता है। मैं किसी एक बिजनेस हाउस का नाम नहीं ले रहा हूं। इस प्रकार की अनेकों कम्पनियां हैं। आज जो इंसेंटिव, कंसेशंस बडी कंपनियों को दिए जाते हैं क्या उसका मकसद पूरा होता है ? जिस मकसद से उनको कंसेशंस दिए जाते हैं क्या बाद में उसकी प्रगति की जांच की जाती है। क्या यह देखा जाता है कि इतना प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया है, इतना एक्सपोर्ट किया है, इतनी विदेशी मुद्रा की बचत की है ? यह काम नहीं हो रहा है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश में कुछ इलाके आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। 1960 में पण्डित जवाहरलाल नेहरू की दखलंदाजी से एक पटेल कमेटी बनी थी। उसके बाद फिर कोई ध्यान इस क्षेत्र के विकास के लिये नहीं दिया गया है। जनसंख्या का सबसे अधिक भार इस क्षेत्र पर है। उद्योगपति इस क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। यातायात के सबसे कम साधन वहां पर हैं। सबसे ज्यादा गरीब मगर मेहनती लोग यहां पर हैं। स्वतन्त्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान इस क्षेत्र का रहा है। आजमगढ़, मधुबन, बलिया, गोरखपुर, चौराचौरी, कितने ही नाम गिना सकता हूं। यहां से बहादुर किसानों और मजदूरों के बेटे आगे बढ़े थे। आज इस इलाके पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक कमीशन बनाने की आवश्यकता है। किस तरह से सुविधाएं वहां पर पहुंचाई जाएं ताकि वहां पर उद्योग-धंधे लग सकें। साधनों का अभाव है, रेलवे लाइन नहीं है, सड़कें कम हैं, बिजली की उचित व्यवस्था नहीं है। पुराने उद्योग धंधे, जैसे बुनकर उद्योग आदि तबाह हो रहे हैं। इनका किस तरह से फिर से विकास किया जाए। इन सारी चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भारत के वित्त मन्त्री एक बार फिर इस बात पर पुनर्विचार करें कि हमारी मौलिक समस्याएं क्यों हल नहीं हो रही हैं। आर्थिक विकास के लिए करों के ढांचे में किस तरह से परिवर्तन किया जाए। समुचित साधनों का किस तरह से सही उपयोग किया जाए ताकि हम लोगों की रोजी-रोटी की समस्या को हल कर सकें। इसके लिए स्ट्रक्चर में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, उस पर विचार किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

15.30 hrs.

COMMITTEE OF PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-EIGHTH REPORT

MR. DEPUTY SPEAKER : We take up Private Members' Business. Shri Rupchand Pal.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : I beg to move :

> "That this House do agree with the Fifty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th April, 1983."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That this House do agree with the Fifty-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th April, 1983."

The motion was adopted.